# सीएए को लेकर अमित शाह का केजरीवाल पर पलटवार

**निशाना**

**गृह मंत्री ने कहा, केजरीवाल ने कानून नहीं पढ़ा है**

**नई दिल्ली, विशेष संवाददाता।** गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सीएए को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। गृहमंत्री ने कहा कि केजरीवाल के मुताबिक सीएए लागू करने से चोरी और दुष्कर्म के अपराधों में वृद्धि होगी।

एक टीवी कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा, केजरीवाल ने कानून नहीं पढ़ा है। वह बगैर पढ़े-लिखे बोलने में माहिर हैं। कानून में लिखा है कि 31 दिसंबर 2014 तक जो शरणार्थी भारत आए हैं, उनके लिए यह कानून है। शरणार्थियों को जेब कतरा और दुष्कर्मी कहना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, केजरीवाल बांग्लादेश से आए घुसपैठियों पर नहीं बोलते।

घुसपैठिए और शरणार्थियों में बड़ा अंतर है। जो देश में गैर-कानूनी तरीके से आते हैं, वे घुसपैठिया होते हैं। देश इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। जो शरण में आता है, धार्मिक प्रताणना के कारण आता है, अपने परिवार की बच्चियों की रक्षा के लिए आता है, अपने धर्म की रक्षा के लिए आता है, इसकी घुसपैठिया के साथ कभी भी तुलना नहीं कर सकते।

वहीं, केजरीवाल को ईडी के समन के सवाल को अमित शाह ने यह कहते हुए टाल दिया कि ईडी के सवाल मुझसे क्यों पूछते है। के कविता के मामले में भी उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के काम का हवाला देकर सीधा जवाब नहीं दिया।

## अमेरिका का चिंतित होना अनुचित : केंद्र

**नई दिल्ली, विसं।** भारत ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर अमेरिकी चिंताओं को खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया और कहा कि अमेरिका तथ्यों से वाकिफ नहीं है।

गुरुवार को अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा था कि सीएए को अधिसूचित किए जाने को लेकर वह चिंतित है तथा इसके क्रियान्वयन पर नजदीकी से नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने शुक्रवार को साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि सीएए भारत का आंतरिक मामला है। यह भारत की मानवाधिकारों के प्रति हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के उन उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों- हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई- समुदायों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके थे।

## याचिका पर सुनवाई को अदालत सहमत

**नई दिल्ली।** उच्चतम न्यायालय केंद्र को नागरिकता संशोधन नियमावली, 2024 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमत हो गया।

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया। दलील में कहा गया है कि विस्थापित हिंदुओं को नागरिकता दिए जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता है, इसलिए इन मुद्दों पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है।

## देश 30s

### सेना में अपाचे का पहला स्क्वाड्रन

**नई दिल्ली।** भारतीय सेना ने पश्चिमी क्षेत्र में जमीनी अभियानों का समर्थन करने के लिए शुक्रवार को राजस्थान में अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का पहला स्क्वाड्रन खड़ा किया। सूत्रों ने बताया कि स्क्वाड्रन का गठन जोधपुर में किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि भारतीय सेना ने शुक्रवार को आर्मी एविएशन कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अजय सूरी की उपस्थिति में अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का पहला स्क्वाड्रन तैयार किया।

### गूगल की प्ले स्टोर नीति की जांच होगी

**नई दिल्ली।** निष्पक्ष व्यापार नियामक सीसीआई ने शुक्रवार को इंटरनेट-आधारित कंपनी गूगल की प्ले स्टोर मूल्य निर्धारण नीति में कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के संबंध में जांच के आदेश दिए। सीसीआई ने इस आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता मुख्य रूप से गूगल के स्वामित्व वाले ऐप स्टोर 'गूगल प्ले स्टोर' की भुगतान नीतियों से व्यथित हैं।

### केंद्र के विज्ञापनों पर टीएमसी ने आपत्ति जताई

**कोलकाता।** तृणमूल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए भाजपा नीत केंद्र सरकार के विज्ञापनों पर आपत्ति जतायी है। इनमें विज्ञापनों में भाजपा ने विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल को निधि आवंटित करने का दावा किया है। टीएमसी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को इस संबंध मं एक पत्र लिखा।

### विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित करें : उमर

**श्रीनगर।** नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि निर्वाचन आयोग को जम्मू-कश्मीर में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी घोषणा करनी चाहिए। अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा, हमें चुनाव आयोग से कोई अपेक्षा नहीं है। चुनाव आयोग को लोकतंत्र को बनाए रखने के अपने मिशन के हिस्से के रूप में भूमिका निभानी चाहिए।

### भोपाल गैस त्रासदी के चार दशक भूजल प्रदूषित

**नई दिल्ली।** भोपाल गैस त्रासदी के चार दशक बाद भी यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र के पास के कुछ स्थानों के भूमिगत जल में भारी धातुओं की उच्च सांद्रता अब भी बरकरार है। सीजीडब्ल्यूए की नयी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

### केरल में कांग्रेस-वामपंथी दल पर पीएम का करारा प्रहार, कहा- इस बार कमल खिलेगा

# मुसीबत में फंसे हर भारतीय के साथ सरकार खड़ी रहेगी : मोदी

**संकल्प**

**पथानामथिट्टा (केरल), एजेंसी।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि मुसीबत में फंसे हर भारतीय के साथ सरकार मजबूती से खड़ी रहेगी। यही मोदी की गारंटी है। एनडीए कार्यकर्ताओं और समर्थकों की रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कोविड-19 महामारी सहित विभिन्न उदाहरणों का जिक्र करते हुए कही। उस दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को देश वापस लाया गया था।

केरल के सत्ताधारी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) को 'ठग' करार देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में दोनों एक-दूसरे का विरोधी होने का दिखावा करते हैं, जबकि दिल्ली में गले मिलते हैं। उन्होंने कहा कि केरल के लोग इनकी सच्चाई समझ गए हैं।

मोदी ने कहा कि पथानामथिट्टा का उत्साह बता रहा है कि इस बार केरल में 'कमल' खिलने वाला है। उन्होंने कहा कि केरल के लोग राज्य में शासन करने वाली भ्रष्ट और अक्षम सरकारों के कारण पीड़ित हैं। आगामी चुनावों में राजग पिछले रिकॉर्ड तोड़कर केंद्र की सत्ता में आएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम को हैदराबाद के मल्काजगिरि लोकसभा क्षेत्र में रोड शो किया। • प्रेट्र

## 'ऐतिहासिक फैसले लेने से हम चूके नहीं'

**नई दिल्ली, एजेंसी।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद पर कठोर प्रहार जैसे अनेक ऐतिहासिक फैसले लेने से नहीं चूकी। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले देश के नाम लिखे पत्र में उन्होंने यह बात कही।

नरेंद्र मोदी ने लिखा, यह आपका विश्वास और समर्थन ही था कि जीएसटी लागू करना, 370 समाप्त करना, तीन तलाक पर नया कानून, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे बड़े फैसले हमने लिए। मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन से जुड़ा यह मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है।

# विकास कार्यों के दम पर देश विश्वगुरु बनेगा: राजनाथ

**विश्वास**

**चतरा (झारखंड), एजेंसी।** रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि वे दिन दूर नहीं हैं, जब भारत में रामराज्य स्थापित होगा और देश 2027 तक दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए विकास कार्यों के दम पर भारत उनके नेतृत्व में विश्वगुरु बनेगा।

सिंह ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के लागू होने पर भाजपा को सांप्रदायिक बताने वालों पर भी निशाना साधा और यह सवाल किया कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी किन परिस्थितियों में लगभग 23 प्रतिशत से घटकर लगभग 3 प्रतिशत हो गई।

राज्य की राजधानी रांची से लगभग 160 किलोमीटर दूर इटखोरी में एक रैली को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि अयोध्या में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अब भारत में रामराज्य की स्थापना होगी... रामलला टेंट से अपने महल में पहुंच गए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों के दम पर भारत उनके नेतृत्व में विश्वगुरु बनेगा और यह भगवान की इच्छा है कि वह न केवल तीसरी बार बल्कि चौथी बार भी प्रधानमंत्री बने रहें।

उन्होंने सीएए पर कहा कि हिंदू, सिख, ईसाई और पारसियों सहित अल्पसंख्यक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे थे और शरण के लिए भारत आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें नागरिकता देने का फैसला किया...इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक करार दिया गया।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए सिंह ने कहा कि यह भारत के इतिहास में अभूतपूर्व घटना है कि एक मुख्यमंत्री ही लापता हो गया लेकिन अब वह भ्रष्टाचार के आरोप में सलाखों के पीछे हैं। सिंह ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों के उलट भाजपा सरकार पर कोई भी भ्रष्टाचार को लेकर उंगली नहीं उठा सकता।

### रक्षा मंत्री ने किया नौसेना भवन का उद्घाटन

**नई दिल्ली।** रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली छावनी में

भारतीय नौसेना के नए अत्याधुनिक मुख्यालय 'नौसेना भवन' का उद्घाटन किया। यह भवन आधुनिक सुविधाओं और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यह नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि इसने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया है।

# सख्ती : के. कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया

**हैदराबाद/नई दिल्ली, एजेंसी।** प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में शुक्रवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को गिरफ्तार कर लिया। संघीय एजेंसी के सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को पूछताछ के लिए दिल्ली लाया जा रहा है। इससे पहले दिन में ईडी अधिकारियों ने हैदराबाद में कविता के परिसरों पर छापेमारी की।

बीआरएस नेता और पूर्व मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हैदराबाद में बताया कि कविता को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें उड़ान से दिल्ली ले जाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम पूर्व नियोजित था। गिरफ्तारी के बाद कविता के आवास पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व मंत्री समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुट गए और नारेबाजी की।

### अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट से जारी समन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी। इसमें व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी गई थी। न्यायालय ने कहा कि मुख्यमंत्री इसके लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। ब्योरा P04

## बिग बी की सेहत को लेकर अटकलें

**मुंबई, एजेंसी।** अभिनेता अमिताभ बच्चन के पैर में खून का थक्का जमने या धमनी अवरुद्ध होने के कारण एंजियोप्लास्टी किए जाने से जुड़ी कुछ खबरें मीडिया में आने के बाद शुक्रवार को उनके शुभचिंतकों ने सोशल मीडिया मंचों पर चिंता व्यक्त की।

अटकलों के अनुसार, अभिनेता को शुक्रवार सुबह कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया [illegible]

## नागरिकता आवेदन के लिए ऐप शुरू

**नई दिल्ली, एजेंसी।** केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को 'सीएए-2019' नाम से मोबाइल ऐप शुरू किया। यह ऐप पात्र लोगों को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए)-2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान करेगा।

[illegible] के प्रवक्ता के अनुसार, एप्लिकेशन को 'गूगल प्ले स्टोर' या केंद्र सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए पोर्टल शुरू किया था। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

# इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी मिली

**नई दिल्ली, एजेंसी।** सरकार ने भारत को विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को मंजूरी दे दी जिसमें न्यूनतम 50 करोड़ डॉलर (4,150 करोड़ रुपये) के निवेश के साथ देश में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को शुल्क में रियायतें दी जाएंगी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि ईवी नीति के जरिये भारत को ईवी के विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने और टेस्ला समेत विभिन्न वैश्विक ईवी विनिर्माताओं से निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया गया है।

आयात के लिए स्वीकृत ईवी की कुल संख्या पर शुल्क में दी गई रियायत उस कंपनी की निवेश राशि या पीएलआई योजना के तहत प्रोत्साहन राशि 6,484 करोड़ रुपये में से जो भी कम हो, तक सीमित होगा। इसके मुताबिक, यदि निवेश 80 करोड़ डालर या उससे अधिक है, तो प्रति वर्ष अधिकतम 8,000 की दर से अधिकतम 40,000 ईवी के आयात की अनुमति होगी।

इस ई-वाहन नीति के बारे में टिप्पणी करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत जारी की गई इस नई नीति से विश्व शक्ति बनकर उभरेगा। घरेलू ही नहीं, विदेशी निर्माता भी भारत को निर्माण का केंद्र बनाएंगे।

### नीति के फायदे

- नवीनतम तकनीक तक पहुंच, 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा, अर्थव्यवस्था का विस्तार,
- स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से ईवी परिवेश को मजबूती, कम लागत पर उत्पादन की उच्च मात्रा
- आयात में कटौती, कच्चे तेल के आयात में कमी,व्यापार घाटा कम होगा, वायु प्रदूषण कम होगा

### आयात कर में मिलेगी छूट

इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाएगा। बशर्ते ईवी की कीमत 35,000 डॉलर (लगभग 29 लाख रुपये) से अधिक न हो। वर्तमान में केंद्र सरकार भारत में लाई जाने वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 70 से 100 प्रतिशत आयात कर वसूलती है।

# पेटीएम ऐप पर पांच नए हैंडल पेश

**राहत**

**नई दिल्ली, एजेंसी।** पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस को यूपीआई लेनदेन जारी रखने के लिए चार बैंकों के साथ साझेदारी में पांच हैंडल मिले हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने पेटीएम को हाल ही में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर (टीपीएपी) के रूप में यूपीआई सेवाओं में भाग लेने की अनुमति दी है।

इससे पहले पेटीएम के यूपीआई लेनदेन पेटीएम पेमेंट्स बैंक के माध्यम से किए जा रहे थे। पीपीबीएल को भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 मार्च के बाद किसी भी ग्राहक खाते में जमा, क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया है।

आरबीआई की इस कार्रवाई के बाद पेटीएम ने अपनी यूपीआई सुविधा जारी रखने के लिए चार बैंकों से हाथ मिलाया है। पेटीएम के प्रवक्ता ने कहा कि उपयोगकर्ता अपनी ओर से कोई बदलाव किए बिना पेटीएम हैंडल का उपयोग करना जारी रख सकते हैं।

### ऐसे प्रयोग कर सकेंगे

- वर्तमान में कंपनी का मौजूदा हैंडल **@paytm** है। इससे कोई बदलाव किए बिना आसानी से भुगतान कर सकते हैं।
- यस बैंक **@ptyes** और एक्सिस बैंक **@ptaxis** हैंडल का विकल्प मिलेगा। ये दोनों सक्रिय हो गए हैं।
- इसी तरह एचडीएफसी **@pthdfc** और एसबीआई **@ptsbi** के हैंडल दिखेंगे। ये अभी सक्रिय नहीं हुए हैं।

## येदियुरप्पा पर दर्ज पॉक्सो केस की जांच सीआईडी को

**बेंगलुरु, एजेंसी।** पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बी.एस. येदियुरप्पा के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी को शुक्रवार को आगे की जांच के लिए आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को सौंप दिया गया।

पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने अपने संदेश में बेंगलुरु पुलिस को बताया कि मामला तत्काल प्रभाव से आगे की जांच के लिए सीआईडी को सौंप दिया गया है।

पुलिस के अनुसार, येदियुरप्पा के खिलाफ 17 वर्षीय एक लड़की की मां की शिकायत पर पॉक्सो कानून की धारा आठ और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

# सड़क हादसे में डेढ़ लाख तक फ्री इलाज

**नई दिल्ली, विशेष संवाददाता।** सड़क हादसों में घायलों की जान बचाने का अभियान एक कदम आगे बढ़ा।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को चंडीगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू की। इससे तहत घायलों को डेढ़ लाख रुपये तक मुफ्त इलाज मिलेगा। जल्द इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य सड़क हादसों में घायल लोगों को समय पर इलाज उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि घायल व्यक्ति सात दिन तक निजी अस्पताल या नर्सिंग होम में अपना मुफ्त उपचार करा सकेंगे।

### पहला घंटा अहम

अध्ययन में साबित हुआ है कि दुर्घटना के पहले एक घंटे में इलाज मिलने से कुल मौतों में से 50% को रोका जा सकता है। 2022 में देश में सड़क हादसों में 1.68 लाख मौतें हुईं, जो सर्वाधिक है। केंद्र ने मुफ्त इलाज के लिए 21 हजार निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है।


**मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण**
प्रथम तल, पंचायतीराज निदेशालय, आई०टी० पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून

संख्या : 2535/I1-02(xix)-2/ITCO/URRDA/23 Dated : 15.03.2024

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
ई–निविदा सूचना–38 / 2023–24

मा0 राज्यपाल उत्तराखण्ड की ओर से मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, द्वारा ई–निविदा के माध्यम से मद आधारित दरों पर जनपद– **पिथौरागढ़**, में पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत 03 पैकेज, कुल लागत **रू0 20.33 करोड़**, पंचवर्षीय अनुरक्षण सहित, की निविदाएं पात्र ठेकेदारों (श्रेणी–ए एवं अधिक), जो लोक निर्माण विभाग / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा सकमक्ष में पंजीकृत हों, से आमंत्रित की जाती है।*

**ई–निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रण की तिथि** : 18–03–2024.

**निविदा प्रपत्र की उपलब्धता एवं जमा किये जाने की विधि** :– निविदा प्रपत्र ऑनलाइन उपलब्ध हैं तथा www.pmgsytendersuk.gov.in में ऑनलाइन ही जमा किये जाने चाहिए। निविदादाता को वेबसाइट में पंजीकरण कराना होगा, जोकि निशुल्क है। निविदा को जमा करने हेतु निविदादाता के पास अधिकृत प्रमाणीकरण संस्था (Certifying Authorities) द्वारा निर्गत डी0एस0सी0 (Digital Signature Certificate) होना चाहिए।

निविदादाता द्वारा आई0टी0बी0 के प्रस्तर– 4.4बी (ii) के अनुसार प्रस्तुत अभिलेखों के सही होने सम्बन्धी शपथपत्र मूल रूप में SBD/MBD में वर्णित **सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय में निविदा जमा करने (Submission of Bid) की तिथि व समय से पूर्व (विश्व बैंक पोषित कार्यों हेतु) तथा तकनीकी बिड (Technical Bid) खुलने की तिथि से विलम्बतम तीन कार्यदिवस के अन्दर (सामान्य पी०एम०जी०एस०वाई० के कार्यों हेतु) पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।** उक्त अभिलेख मूल रूप से निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त न होने की दशा में दी गई निविदा को अमान्य घोषित कर दिया जायेगा। निविदाएं जमा करने की तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त होने वाले मूल अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

**ई–निविदा के माध्यम से निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय** : 15–04–2024 अपराह्न 1:00 बजे तक
अधिक जानकारी हेतु कृपया **www.pmgsytendersuk.gov.in** देखें।

मुख्य अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।

* निविदादाता, जो पंजीकृत नहीं है, वे भी निविदा दे सकते हैं, किन्तु सफल निविदादाता को अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने से पूर्व उचित श्रेणी मे सक्षम प्राधिकारी से पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

**नोट टेण्डर की प्रक्रिया में मदद एवं जानकारी हेतु कृपया 0135–2675725 में प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।**



**Information Technology Development Agency (ITDA)**
Department of IT, Good Governance & Science Technology
Government of Uttarakhand Ph-0135-2608330 /diritda-uk@nic.in

Reference No: 12865/ITDA Date: 15.03.2024

Advertisement for Recruitment to the Post of Manager (Procurement & Contract Management), ITDA

ITDA invites qualified and experienced professionals/Staff for the following post on Contract basis.

| Sr. No. | Name of Post | No. of Post | Source/mode of recruitment |
|---|---|---|---|
| 1. | Manager (Procurement & Contract Management), ITDA | 01 | Contractual |

Last date for submitting application is, 02 April 2024 till 5:00 PM
The applications submission mode is online only through https://itda.uk.gov.in/career; physical submissions of applications are not allowed.

Director



**उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि०**
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर (गढ़वाल) दूरभाषः 01346–252137,
Email: dgmsri.upcl@yahoo.com कॉरपोरेट आई0डी0 संख्या (CIN) U40109UP2001SGC025867/2358

**ई–निविदा आमंत्रण सूचना** दिनांकः 15.03.2024

अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा इस मण्डल के अन्तर्गत निम्न ई–निविदा आमंत्रित की जाती हैः।

**51 / विविमश्री / 2023–24**–Replacement of existing 33 KV ACSR Dog Conductor with 33 KV AAAC AL-59, 241sq mm covered conductor at different work site from 33 KV Bagwan to 33 KV Lingwana (Jamnikhal) under EDD Srinagar (G.) on Semi-Turnkey Basis.

अन्य विवरण के लिये कृपया हमारी वेबसाईट www.uktenders.gov.in देखें एवं ई–निविदा के सम्बन्ध में किसी भी जानकारी के लिए कृपया फोन नं0 01346–252137 पर सम्पर्क करें।

पत्रांकः 458 / वि0वि0म0श्री0 / टी–9 अधीक्षण अभियन्ता

**राष्ट्र हित में बिजली बचावें** (टोल फ्री नं0 :-1800 419 0405) विद्युत चोरी की सूचना हेतु सतर्कता अधिकारी से फैक्स 0135–2760911 एवं मोबाइल +91–8958811999 पर एस0एम0एस0 द्वारा रिपोर्ट करें।



**कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट देहरादून**

पत्रांकः 309/बीस-62 (2014-17)जेए **-: निविदा सूचना :-** दिनांकः 15 मार्च, 2024

जनपद देहरादून में निम्नांकित कार्य हेतु मोहरबंद निविदायें जिला कार्यालय (न्याय अनुभाग) में दिनांक 31-03-2024 को समय 02:00 बजे अपराहन तक सम्बन्धित ठेकेदार से आमंत्रित की जाती है, निविदा खोले जानें की तिथि के सम्बन्ध में निविदाकारों को पृथक से सूचित किया जायेगा। निविदा नियत तिथि एवं ससमय तक किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय के अन्दर प्राप्त किये जायेगें। निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक में एफ०डी०आर० के रूप में जो जिलाधिकारी देहरादून के पदनाम पर बंधक होगी मान्य होगी। बिना धरोहर राशि के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

| क्रम सं० | कार्य का नाम | धरोहर धनराशि | निविदा की वैद्यता की अवधि |
|---|---|---|---|
| 2. | जनपद देहरादून में अपराधिक मामलो अभिज्ञान हेतु चोरी के माल में वस्तुओ के सम्भरण करने के लिये माल ठेकेदार की नियुक्ति | 10,000/- रू0 | तीन वर्ष के लिये |

**निविदा की शर्तें:-**

1. सशर्त निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी।
2. बिना कारण बताये किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
3. निविदा प्रपत्र के साथ जो भी विशिष्टियां दी जायेगी उसी के अनुरूप कार्य/आपूर्ति करनी होंगी।
4. स्वीकृत निविदादाता को स्वीकृति की सूचना की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध पत्र हेतु उपस्थित होना होगा एवं अनुबन्ध के समय शासनादेशों के अनुसार स्टाम्प शुल्क एवं 10 प्रतिशत जमानत की धनराशि जमा करानी होगी अन्यथा धरोहर की धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
5. कार्य/आपूर्ति त्रुटिपूर्ण होने अथवा निर्धारित विशिष्टयों के अनुसार न होने की दशा में कोई भुगतान नहीं किया जायेगा एवं जमानती धनराशि जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
6. सभी कार्यों की दर अंको एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से दर्शानी होगी।
7. शासन द्वारा लिये जाने वाले समस्त टैक्स (यदि कोई हो) ठेकेदार को वहन करने होगे जो बिल से काट जा सकते है।

**(सोनिका), जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।**



**कार्यालय निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानीसेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून**

पत्रांक-12809/जी-394/2023-24 **विज्ञप्ति** दिनांक- 15 मार्च 2024

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा विभाग उत्तराखण्ड के अधीन राज्य के 8 उच्चीकृत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण एवं अन्य समस्त जानकारी विभाग की वेबसाईट www.uttarakhandayurved.co.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र दिनांक **22 अप्रैल 2024** सांय 5:00 बजे तक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड, डाण्डा लखौण्ड निकट-आईटी पार्क सहत्रधारा रोड़, देहरादून के कार्यालय में पंजीकृत डाक/ स्पीट पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किये जायेगें।

**डा० विजय कुमार जोगदण्डे**
**निदेशक**

## JOB DESCRIPTION:

| # | Particular | Description |
|---|---|---|
| 01 | Position Name | Manager - Contract Management & Procurement |
| 02 | Domain Expertise | Contract Management & Procurement |
| 03 | Number of Openings | 01 |
| 04 | Positioned at | ITDA, Dehradun |
| 05 | Engagement Type | Contractual |
| 06 | Engagement Terms | Minimum Period for 03Years + 2Year based on performance |
| 07 | Leaves | As per prevailing Organisation Policy |
| 08 | Compensation/ Professional Fees | INR 1,15,000.00 |
| 09 | Other provisions | Laptop or Desktop, Work Space, any other requisite to fulfil the duties smoothly. |
| 10 | Mode of Application | **ONLINE ONLY (https://itda.uk.gov.in/career)** |
| 11 | Last date of Application (until extended) | **02/Apr/2024 05:00 PM** |

## Qualifications:

**Educational Background:**

- Graduate & MBA in Finance from UGC approved University in regular mode
- Having Experience of Procurement & Store Management Contract Management & Contract Legal
- Having knowledge of Word, Power Point, Excel
- Minimum **05 Years' experience** in Procurement & Contract Management
- Having work experience on Green Notesheet/ Noting writing

## Key Responsibilities:

- Draft, evaluate, negotiate and execute contracts
- Establish and maintain supplier relationships by serving as a single point of contact for contractual matters
- Manage record keeping for all contract-related correspondence and documentation
- Provide contract-related issue resolution, both internally and externally
- Monitor and complete contract close-out, extension or renewal, as appropriate
- Communicate contract-related information to all stakeholders
- Assist in compliance with mandatory standards & prevailing rules

## Desirable activities performed/ tasked:

- **In-depth knowledge of Uttarakhand State Procurement Rules.**
- **In-depth knowledge & exposure to CVC guidelines.**
- Awareness of ADB Procurement Policy/Guidelines for funded projects.
- Experience of GeM & Uttarakhand state e-Procurement Portal.
- Experience of studying DPR & preparation of RFP/RFQ/EOI/etc.
- Experience in project procurement life-cycle in government projects, preferable of IT projects.
- Demonstrated negotiation and problem-solving skills
- Strong contract modeling software skills
- Robust skills in Microsoft Office software, including Word, Excel, PowerPoint, Access, Project and Visio
- Ability to meet project objectives within designated constraints